RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

Youngster

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · MAY 2020 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

भाई भतीजावाद के दलदल में धंसता समाज

तन्नू शर्मा नई दिल्ली: भाई भतीजावाद से तो आप सभी परिचित हैं और होंगे भी कैसे नहीं आजकल काफी ट्रेंडिंग में जो है, अपनों के लिए पक्षपात तो कई सालों से चलता आ रहा है और हर छोटे बड़े क्षेत्र में होता आ रहा है न केवल भारत में बल्कि अन्य देशो में भी ऐसा हो रहा है और अब तो ऐसा भी कह सकते है की भाई–भतीजावाद के साथ भ्रष्टाचार हाथ से हाथ मिला कर चल रहा है। राजनीति, व्यापार और फिल्म जगत में नेपोटिज्म आम ही है। सबका मानना यह है कि अभिनेता के बच्चे है तो अभिनेता ही बनेगें, और अगर चाचा विधायक है तो भतीजा भी विधायक बनने की चाह रखता है। नौकरी नहीं मिल रही तो पहुंच के माध्यम से सिफारिश लगवा के नौकरी मिल जाएगी चाहे वो इसके के लायक हो या न हों। भाई भतीजावाद का विचार लोगों के दिमाग में इस तरह से घर कर बैठा है कि लोग अपनी पहचान का गलत फायदा उठा कर भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें देश से मतलब नहीं चाहे भ्रष्टाचार दीमक की तरह इन्सानियत को खा ले, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने से। ऐसे कई युवा हैं जो योग्यता से तो भरपूर होते हैं परन्तु स्वजनों को लेकर होते पक्षपात के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है ताकि उनका स्थान किसी और को दे दिया जा सके। कई ऐसे लोग हैं जो योग्यता में कहीं ज्यादा पीछे हैं, पर पहुँच सबसे आगे। सभी ने अपने भाई भतीजावाद के चेहरे के ऊपर झूठा इंसानियत के मुखौटा पहन रखा है कहीं स्वजन–पक्षपात खुलेआम सबके सामने होता है, तो कहीं चुपके से होता है। हमें यह मुखौटा उतार फेंकना होगा ताकि इसके वजह से फिर से कोई योग्य व्यक्ति हिम्मत हार कर जान न गवां बैठे।

आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

श्रेय आर्या: आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को लेकर यह शर्त रखी थी यह कानून 10 वर्षों तक लागू रहेगा और अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया कानून अब जनता लॉलीपॉप की तरह पकड़ाया जा रहा है। हाल ही में नीट परीक्षाओं में आरक्षण को लेकर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक याचिका डाली गई थी, जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि **"आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।"** कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जिस तरह तमिलनाडु सरकार 50 प्रतिशत् ओबीसी आरक्षण अपने राज्य में देती है ठीक उसी प्रकार पूरे देश में मेडिकल की सीटों पर 50 प्रतिशत् का ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। आज आरक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं उन्होंने इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर भुना लिया है। डीएमके, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस आदि ये वो तमाम राजनीतिक दल हैं जो कभी भी किसी मुद्दे पर एकमत नहीं होते पर जब बात आरक्षण की आई तो सभी की रोटियां एक ही चूल्हे पर सिकने लगी। इन सभी ने मिलकर एक बार में आवाज लगाई कि इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकारों के हनन का मामला मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी इन सभी कट्टर विरोधी पार्टियों को एक साथ देख कर हैरान था।

देश के हालात इस वक्त बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं एक ओर कोरोना महामारी का संकट है तो दूसरी ओर चीन सीमा पर बढ़ता तनाव, लेकिन ऐसे हालातों में भी सभी पार्टियों ने अपनी–अपनी तरफ से बड़े ही बेहतरीन ढंग से राजनीति को अंजाम दिया है। 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन फिर भी देश में एक बहुत बड़ा तबका है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है उसे अभी तक इसका कोई भी लाभ नहीं मिल सका है। इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध दोनों ही मामलों में राजनीतिक पार्टियों ने अपना फायदा देखा है, इस पर बात करते हुए अगर किसी ने सवाल उठा दिए तो उसे दलितों और पिछड़े वर्ग का दोषी करार दिया जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में जिस सुविधा का दायरा वक्त के साथ कम करने की बात कही थी आज उसने हर क्षेत्र में अपने पैर पसार लिए हैं।

हमारे देश के राजनेता शुरू से ही आरक्षण के बीज बोकर मन मुताबिक फसल काटते आ रहे हैं। आरक्षण को जातिवाद की राजनीति में बदलकर देश और जनता दोनों को ही लूटा गया है। देश में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं आमदनी के आधार पर देना चाहिए भारत के लगभग एक चौथाई जनसंख्या गरीब है और साक्षरता दर महज 75 प्रतिशत्।

ऐसे में जो समाज के पिछड़े और अनपढ़ तबके से आते हैं उन्हें इस आरक्षण की बहुत आवश्यकता है फिर चाहे वह किसी भी जाति–धर्म के हों। जरूरत है तो बाबा साहब के नाम का कॉपीराइट रखने वाली दलों को उनके मूल विचार समझने की।

बिना लक्षण वाला कोरोना लोगों को असमंजस में डाल रहा है

आयुषी बिष्ट, दिल्ली: एसिंप्टोमेटिक! यह शब्द भी कोरोना काल में एक नई मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इससे उलझन और ज्यादा बढ़ रही है। कोरोना के बेगैर लक्षण वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बगैर लक्षण वाले मरीजों में संक्रमण फैलता है, या उन मरीजों से संक्रमण होता है कि नहीं होता।

हमारी देश की मेडिकल रिसर्च संस्था आइसीएमआर अब इन सवालों पर रिसर्च कर रही है। दुनिया को गाइडलाइन जारी करने वाला वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइज़ेशन खुद ही भ्रम में है। मुंबई बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मृत्यु हो गई। इससे एक दिन पहले तक वह ड्यूटी पर तैनात थे। शिरीष दीक्षित की मौत कोरोना वायरस से हुई लेकिन उनको वायरस के कोई भी लक्षण नहीं थे। बिना लक्षण वाले मरीजों को एसिंप्टोमेटिक मरीज कहते हैं। बहुत सारे मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखते हैं, लिहाजा रोगी की पहचान करनी मुश्किल होती है और इसमें कई बार अचानक तबीयत बिगड़ती है और मौत हो जाती है। कई एसिंप्टोमेटिक मरीज ऐसे हैं जो खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। भारत में भी आईसीएमआर के हवाले से एक बड़ी खबर आई की रैंडम टेस्टिंग में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं।

भारत के मशहूर हार्ट विशेषज्ञ केके अग्रवाल का कहना है कि "जो आइसीएमआर ने कहा है कि हमने 70 जिलों में 34,000 लोगों के ब्लड टेस्ट किए और उसमें 30 प्रतिशत लोगों में साइलेंट बीमारी पाई गई। इसे हम प्रेवेलेंस इन सोसाइटी बोलते है। यह बिल्कुल सही है बाकी विदेशों में भी ऐसा ही हो रहा है।" भारत के वह 30 फीसदी मरीज क्या बगैर दवा लिए ठीक हो गए? इस पर आइसीएमआर की जांच जारी है। एसिंप्टोमेटिक मरीजों को लेकर कई सवाल है जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मरीजों से संक्रमण फैलता है? इसे लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, रिसर्च जारी है। डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल टीम हेड मारिया वान ने कहा बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण का खतरा बेहद कम होता है, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्होंने अपनी ही बात काटते हुए कहा कि संक्रमण फैल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के इस

समय में आपको क्या करना चाहिए? जवाब बिल्कुल सीधा है। आपको अलर्ट रहना है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है क्योंकि यही है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने से शरीर में एंटीबॉडी बनती है यह खुद–ब–खुद वायरस से लड़ती रहती है। आपको पता भी नहीं लगता और शरीर को अटैक करने वाले वायरस का खात्मा हो जाता है।

सौंदर्य की कस्तूरी को खोजता मानव रूपी हिरण

तनु शर्मा, नई दिल्ली: ऐसा कहा जाता है कि एक हिरण कस्तूरी को हर उस जगह खोजता है जहां उसके पाए जाने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन वह उस कस्तूरी को अपने अंदर नहीं खोजता जो उसी के अंदर पाई जाती है। आजकल इंसानों का चरित्र या सौंदर्य को लेकर उनकी खोज कुछ इसी प्रकार की हो गई है। कोई भी पूर्ण नहीं होता है, हर एक की जिन्दगी में एक ऐसा पल होता है जब वो अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी का शिकार होता है। जब कोई सौंदर्य के मानकों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे समाज में तरह–तरह की प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है फिर चाहे वो मजाक में बोले हुए शब्द हो या फिर जानबूझकर, जिसका परिणाम ये होता है कि हम खुद पर ही संदेह करने लगते है। आत्म–आलोचनात्मक विचारों में खोए रहते हैं अपने शरीर को तिरस्कृत करते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। इस पर हुए कई सर्वेक्षणों की मानें तो यह सबसे ज्यादा किशोरों में देखा जाता है, वे मशहूर हस्तियों और मीडिया से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी तरह बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते है। यहाँ तक कि किसी का तिरस्कार करने में भी उन्हें कोई शर्म नहीं आती। हमें उनको यह एहसास दिलाना चाहिए

कि शारीरिक रूप से छोटा, मोटा, पतला, लम्बा होना अपमान नहीं है, बल्कि सिर्फ व्यक्ति की विशेषताएं हैं और आपकी ये विशेषताएं आपकी योग्यता नहीं निर्धारित करती।

आज कल सभी आपके त्वचा के रंग से आपकी सुंदरता का पता लगाते हैं, अगर आपका रंग गोरा है तो आप सुन्दर हैं और कालें है तो आप बदसूरत है। आखिर यह कैसी धारणा हुई कि किसी की योग्यता उसके बाहरी स्वरूप से ही होनी चाहिए? इस प्रकार की प्रवृत्ति आजकल महिला और पुरुष दोनों में ही देखी जा रही है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं आप सब विद्या बालन को तो जानते ही है इन्होंने कहानी, तुम्हारी सुलु जैसे कई पिक्चर की हैं और उनको इनके वजन की वजह से कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, अगर वो अपने वजन की वजह से रुक जाती तो क्या इस तरह के बेहतरीन किरदारों को कभी निभा पातीं? किसी ने अगर अब्दुल कलाम को उनके मझले कद और रंग रूप के कारण ना बोल दिया होता तो क्या भारत आज परमाणु शक्ति बन पाता? अगर गांधी जी ने अपने दुबले–पतले शरीर के बारे में सोचा होता तो क्या गांधी जी वे सारे काम कर पाते जो उन्होंने किए?

सबसे पहले हमे यह अंग्रजी में कहे तो बॉडी शेमिंग की धारणा को दिमाग से निकाल फेंकनी होगी। किसी के बाहरी स्वरूप को इतनी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उसके अंदर का इंसान ही हमें दिखना बन्द हो जाये। एक ना एक दिन सभी का बाहरी सौंदर्य खत्म हो जाता है और बच जाता है तो उसका ज्ञान, उसका चरित्र, और भीतर की सुंदरता जिन्हें किसी भी प्रकार के श्रृंगार की जरूरत नहीं।

तालाबंदी में बेरोजगारी की मार झेलती महिलाएं

य.सं. नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है, एहतियातन मार्च माह के अंत से ही पूरे देश में लॉक डाउन जारी हो गया है। अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ी है, लेकिन अब धीरे–धीरे अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। परन्तु लॉकडाउन के पहले ही महीने में हजारों कर्मचारियों के अपनी नौकरी से हाथ धोने की खबरें सामने आ रही थी, जिसका सबसे ज्यादा असर दैनिक श्रम, छोटे–मोटे काम धंधे करके परिवार चलाने वाले लोगों पर हुआ, फिलहाल तो उनके पास भी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। जिन लोगों की नौकरियाँ अचानक चली गयी हैं या लॉकडाउन के कारण रोजगार अचानक बंद हो गया है, उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं जनसंख्या में एक ऐसा वर्ग भी है जो सर्वव्यापी महामारी के पहले से ही शोषित किया जा रहा है। भारत हमेशा से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है जहां महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम अवसर मिले हैं चाहे वो पढाई में हो या नौकरी में हो स एक रिपोर्ट की माने तो 220 मिलियन महिलाओं ने महामारी के वक्त अपनी नौकरी गवां दी है। लिंग के आधार पर असमानता हम सालों से सुनते और देखते हुए आ रहे हैं। यह कोई आज का विषय नहीं है, श्रम शक्ति की भागीदारी में पुरुष महिलाओं में अंतर व्यापक रूप से बढ़ता ही जा रहा है, अब प्रश्न यह उठता है कि जो महिलायें श्रमिक काम में है वो नौकरी के नुकसान की चपेट में पुरुष की तुलना में ज्यादा है कैसे? जी हाँ, महिलाओं को नौकरी में अधिक नुकसान उठाना पड़ा है और नौकरी खोने के डर ने उन्हें और कमजोर बना दिया है। माहवारी का पहला दिन हमेशा ही दर्दनाक होता है ऐसे में कई कम्पनियों के नियम तो ऐसे होते है जहाँ आज भी महिलाओ को छुट्टी नहीं मिलती। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। यह प्रसव की अनुमानित तिथि से आठ सप्ताह पहले से शुरू हो सकती है। आज इतने अवसर मिलने के बाद भी महिलाओं को कमजोर वर्ग में गिना जाता है, महिलाओं को लेकर कई सारे आंदोलन हुए कई सारी चर्चाएं हुई कई सारे योजनाएं भी बनी लेकिन आज भी उन सभी योजनाओं का सफर महज सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित है। आज जरूरत है तो उन योजनाओं को कागजों से उतारकर जमीनी हकीकत बनाने की।

THIS MONTH

May 21, 1991 - Former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated in the midst of a re-election campaign, killed by a bomb hidden in a bouquet of flowers. He had served as prime minister from 1984 to 1989, succeeding his mother, Indira Gandhi, who was assassinated in 1984.

*****

May 1, 2004 - Eight former Communist nations and two Mediterranean countries joined the European Union (EU) marking its largest-ever expansion. The new members included Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, along with the island of Malta and the Greek portion of the island of Cyprus. They joined 15 countries already in the EU, representing in all 450 million persons.

*****

May 2, 2011 - U.S. Special Operations Forces killed Osama bin Laden during a raid on his secret compound in Abbottabad, Pakistan. The raid marked the culmination of a decade-long manhunt for the elusive leader of the al-Qaeda terrorist organization based in the Middle East. Bin Laden had ordered the coordinated aerial attacks of September 11th, , in which four American passenger jets were hijacked then crashed, killing nearly 3,000 persons. Two jets had struck and subsequently collapsed the 110-story Twin Towers of the World Trade Center in York, while another struck the Pentagon building in Washington, D.C. A fourth jet also headed toward Washington had crashed into a field in Pennsylvania as passengers attempted to overpower the hijackers on board.

Compilation:
Ms. Honey Shah

BASICS OF MEDIA

Medium Requirements: All content elements, production elements, and people needed to generate the defined process message.

*****

Process Message: The message actually received by the viewer in the process of watching a television program.

*****

Teleprompter: A prompting device that projects the moving (usually computer-generated) copy over the lens so that the talent can read it without losing eye contact with the viewer. Also called auto cue.

*****

Production Schedule: The calendar that shows the reproduction, production, and postproduction dates and who is doing what, when, and where.

*****

Program Proposal: Written document that outlines the process message and the major aspects of a television presentation.

*****

Treatment: Brief narrative description of a television program.

*****

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

मौसम–कोरोना की मार और सरकारी बेरुखी से चौपट खेती–किसानी

इस बार पश्चिम उत्तरप्रदेश (यूपी) के बिजनौर जिले का किसान सुमित सिंह गेहूं घर लाया तो माथा पकड़कर बैठ गया। दाना कमजोर था और प्रति बीघा करीब आधा गेहूं ही निकल पाया। जबकि लागत हर साल की तरह लगाई। भले ही गेहूं की फसल घर आ गई, लेकिन बाजार में बेचने की हिम्मत प्रतापगढ़ के किसान विनोद सिंह के पास नहीं। नकदी का संकट है। व्यापारी एमएसपी से 200 रुपये कम का भाव लगा रहा है। आसपास कोई सरकारी केंद्र है नहीं। लॉकडाउन के कारण ग्राहक भी नदारद हैं। –किसान तेजपाल ने जैसे–तैसे पांच बीघा गेहूं की फसल तैयार की। कटाई भी की लेकिन मौसम की ऐसी मार पड़ी कि कटी–कटाई फसल खेत में ही रह गई। दाना तो कमजोर और काला होगा ही, खरीदार भी मिलना मुश्किल होगा।

–मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके का किसान जगदीश पाटीदार प्याज की फसल से खुश था लेकिन लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि मुनाफा तो दूर खेत की लागत भी निकलना दूभर हो गई है। शहर में अभी भी 20 से 25 रुपये किलो फुटकर में बिकने वाला प्याज किसान को 4 से 6 रुपये प्रति किलो बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

इन चार उदाहरण के साथ किसानों की मनः स्थिति जानने के बाद कलेजा कांपने लगता है। मध्य प्रदेश में दो दिन तक लाइन में लगे किसान को जब दाना हलका और बेकार बता चलता करने की कोशिश की गई तो उसके मन पर क्या गुजरी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। विरोधस्वरूप लाइन में लगे भूखे–प्यासे किसानों को लाठियां और खानी पड़ीं। छह माह दिन–रात एक कर फसल तैयार करने वाले किसान को सही भाव के लिए धक्के खाने पड़े। प्याज का किसान भी इस समय रो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। मौसम की बेरुखी के बाद कोरोना की मार ने किसानों को दोहरे संकट में डाल दिया है। ऊपर से सरकारी आंकड़ों की बाजीगिरी लगातार किसानों को भरमाने का काम करती है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है।

सरकार ने जानबूझकर बढ़ाए उत्पादन के आंकड़े

किसानों के साथ सरकारें और सरकारी तंत्र हमेशा से ही छल करते आए हैं। इस बार इसका खुलासा हुआ है। हालांकि इसके बाद भी किसान की स्थिति बदलेगी इसमें संदेह ही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि इस वर्ष रबी की फसल के उत्पादन और उत्पादकता में आश्यर्चजनक तरीके से कमी आई है। इस बात का पता इसलिए चला कि खाद, बीज और कीटनाशक का बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार रबी सीजन में कहीं अधिक इस्तेमाल किया गया लेकिन कटाई के वक्त उत्पादन से लेकर उत्पादकता में कमी दर्ज की गई। रबी की कटाई, मड़ाई एवं ओसाई की निगरानी कर रही एजेन्सियों की ओर से जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, उससे यह पता चलता है कि पिछले साल से अधिक रकबा होने के बावजूद गेहूं से लेकर दलहन एवं तिलहन तक के उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी आने जा रही है। उसके बावजूद खरीफ फसलों के उत्पादन लक्ष्य को सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। लक्ष्य में यह बढ़ोतरी खरीफ की हर फसल मसलन धान से लेकर दलहन–तिलहन एवं मोटे अनाजों के उत्पादन तक के लिए की गई है।

आंकड़ों में संशोधन किया गया

प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने खरीफ प्लान के साथ भेजी खुद की रिपोर्ट में न सिर्फ इसे स्वीकार किया है बल्कि रबी के संभावित उत्पादन – उत्पादकता के आंकड़े को संशोधित कर घटाया भी है। साथ केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी संभव है कि फरवरी–मार्च में मौसम में जो बदलाव आया उससे पैदावार घटी है लेकिन परिणामों का विश्लेषण यह बताता है कि इसके पीछे कोई और बड़ा कारण हो सकता है, जो विस्तृत अनुसंधान के बाद ही पता लगे। हालांकि यह बात अगली खरीफ की फसल पर भी लागू होती है क्योंकि लॉकडाउन और खराब मौसम ने असली गणना पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

गणना का तरीका ही गलत

इस बारे में कृषि एवं लागत मूल्य आयोग (सीएसीपी) के पूर्व चेयरमैन डॉ. टी हक का मानना है कि अभी तक देश में किसानों की फसल खरीदने और उसका उचित मूल्य देने के लिए कोई ठोस नीति बनाई ही नहीं गई। कुछ नीतियां बनाई भी गईं उनका किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि वह फाइलों में ही कैद हैं। टी हक का कहना है कि अगले सीजन के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए पिछले सीजन के रकबे और उत्पादन के आधार पर गणना की जाती है जबकि यह आधार ही गलत है क्योंकि देश में अधिकांश खेती मौसम के उतार–चढ़ाव पर निर्भर करती है। उन्होंने माना कि सरकारी तंत्र खेती के डाटा को सरकार की मंशा के अनुरूप गढ़ लेते हैं जबकि वैज्ञानिक विधि से डाटा गलत होने की संभावना कम होती है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा केवल सात से नौ फीसदी किसानों को ही मिलता है लेकिन इससे ऐसा होता है कि बाजार में फसल का मूल्य लगभग स्थिर रहता है। अगर ऐसा न होता तो किसान फसल को कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर होते। उन्होंने बताया कि सरकार के पास फसल रखने की जगह ही नहीं। अगर किसानों को खेती को फायदे का सौदा बनाना है तो इसके लिए हर गांव में प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने होंगे। को–ऑपरेटिव खेती को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों को निजी एजेंसी और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ किसानों को जोड़ना होगा। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि कोरिया जैसा छोटा सा देश वर्ष 1961 में आजाद हुआ। वहां की जोत भारत से कहीं कम है फिर भी तकनीक, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के चलते वहां का किसान तुलनात्मक रूप से 25 गुना ज्यादा खुशहाल है। इमानदारी से नीतियों के लागू होने पर ही किसान का भला होगा।

मौसम ने बिगाड़ा गेहूं उत्पादकता का गणित

इस बार दिसंबर और जनवरी में लगातार खराब मौसम ने गेहूं की उत्पादकता पर जबरदस्त असर डाला इसीलिए सरकारों को भी उत्पादन के बढ़े आंकड़ों को दुरुस्त करने को मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में बारिश ने एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ा। दिसंबर में भी सर्वाधिक आठ दिन कोल्ड वेव रही और बारिश ने रौद्र रूप दिखाया। आंकड़ों के मुताबिक भारत में जनवरी माह में सामान्य से 63 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य भारत इसमें सबसे आगे रहा यहां 84 फीसदी अधिक बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत में 70 और पूर्वी–पूर्वोत्तर भारत में यह प्रतिशत 51 रहा।

इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉ जेपी डबास कहते हैं कि बारिश आधारित इलाकों में तो रबी की फसल को इसका फायदा हुआ लेकिन पश्चिम यूपी या आसपास के इलाकों में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। लगातार बारिश से न तो खाद का अपेक्षित गुण लग पाया और न ही कीटनाशक का। नतीजतन ऐसे इलाकों में गेहूं की फसल कमजोर हुई। जिन इलाकों में तेज हवाएं चलीं और ओलावृष्टि हुई उसका भी नुकसान फसल और किसान दोनों को हुआ।

इस बारे में उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग के सदस्य धर्मेंद्र मलिक भी इत्तेफाक रखते हैं। उनका मानना है कि खराब मौसम की वजह से गेहूं की नर्सरी में प्रस्फुटन नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप गेहूं की बाली कमजोर हुई और उसका उत्पादन पर जबरदस्त असर पड़ा है। उनका मानना है कि 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर निकलने वाला गेहूं इस बार 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर निकल रहा है। इसलिए आंकड़ों को एकत्र कर सरकार से गेहूं किसानों को अलग से प्रति कुंतल के हिसाब से आर्थिक मदद की मांग की जाएगी। बांझ होते खेत भी एक वजह हैं। बदलते मौसम के साथ ही खेती की उर्वरा शक्ति का कम होना भी उत्पादकता कम होने की एक वजह है। उत्तर प्रदेश की मृदा परीक्षण अभियान की रिपोर्ट में कहा गया कि खेतों को स्वस्थ रखने वाला जीवांश कार्बन मिट्टी से गायब हो चुका है। यह हालत एक–दो जिलों की नहीं बल्कि सभी 75 जिलों की है। जहां की मिट्टी में बमुश्किल से 0.25 प्रतिशत ही जीवांश कार्बन है जबकि मानक 0.8 होना चाहिए। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि खेत में जो खाद और पानी लगाया जा रहा है वह व्यर्थ जा रहा है। कृषि जानकारों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। सरकार के पास तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं लेकिन आज तक किसानों के लिए कोई योजना बड़े स्तर पर लागू ही नहीं की गई। जिलों में मृदा परीक्षण के बाद किसानों को जागरूक करने का काम करना चाहिए लेकिन ऐसी योजनाएं लालफीताशाही की भेंट चढ़ जाती हैं। यह हकीकत है कि उत्पादकता बढ़ानी है तो खेत की सेहत सुधारने का काम करना ही होगा।

आतिश कुमार

रबी में हुए नुकसान की स्थिति (उत्पादन लाख टन में)–

फसल	उत्पादन (2018–19)	लक्ष्य (2019–20)	संभावित उत्पादन (2019–20)
गेहूं	380.40	391.48	380.00
मोटा अनाज	4.93	5.91	4.50
दलहन	20.27	27.20	20.50
तिलहन	13.53	14.13	12.50

(स्रोत– उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आंकड़े)

बीजेपी के सामने क्यों फ्लाप हुआ सपा–बसपा गठबंधन

अंदाजे लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सपा–बसपा गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नतीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि नुकसान तो दूर गठबंधन बीजेपी को चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर भी नहीं दे सका।

लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा। साथ ही ये गठबंधन शायद बीजेपी को काफी नुकसान भी पहुंचा दे। लेकिन टक्कर देना तो दूर कई जगह तो ये गठबंधन ठीक से मुकाबले में भी नहीं दिखा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इन पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग इन चुनावों में क्यों काम नहीं कर सकी।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पहचान मुख्य रूप से पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में होती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी के रूप में जानी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इन दलों में दूसरे समुदाय के लोग नहीं हैं या फिर अन्य समुदाय के वोट इन्हें नहीं मिलते हैं लेकिन सालों से इनका पारंपरिक वोट बैंक यही समुदाय रहे हैं। बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व और निष्ठा देश, काल और परिस्थिति पर ही निर्भर होती है।

जहां तक गठबंधन का सवाल है तो सपा और बसपा इस उम्मीद में साथ आई थीं कि उन्हें पिछड़ी और दलित जातियों के वोट के साथ यदि अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों का एकतरफा वोट मिल गया तो पूरे राज्य में राजनीतिक समीकरण इस तरह के हो जाएंगे कि बीजेपी समेत कोई और पार्टी कहीं मुकाबले में ही नहीं दिखेगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधान सभा चुनाव में ये आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे और इन पर मुहर लगा दी पिछले साल हुए फूलपुर, गोरखपुर और कैराना लोकसभा के उपचुनावों ने। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जातियों का यह समीकरण सीटों में तब्दील नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है। वहीं ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि सभी दलित और सभी पिछड़ी जातियां इन्हीं पार्टियों के प्रति निष्ठा रखती हों। बावजूद इसके यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का कोर वोटर समझा जाता है और दलितों में जाटव समुदाय बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन में शामिल थी। इनके साथ यदि मुस्लिमों की आबादी के प्रतिशत को भी जोड़ दिया जाए तो ये करीब पचास प्रतिशत बैठता है।

इसी आंकड़े के साथ गठबंधन के नेता राज्य में लोकसभा की 80 में से कम से कम 60 सीटें जीतने का अनुमान लगाए बैठे थे लेकिन जब परिणाम आए तो गठबंधन को महज 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इनमें भी समाजवादी पार्टी तो महज पांच सीटों पर ही सिमट गई और बसपा के खाते में दस सीटें गईं। बीजेपी को 62 सीटें और उसकी सहयोगी अपना दल को दो सीटें मिलीं। रायबरेली की एकमात्र सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी को जीत हासिल हुई

सपा और बसपा अपने वोट बैंक को एक–दूसरे को दिलाने में नाकाम रहीं, बसपा नेता मायावती को अब तक माना जाता था कि वो अपना वोट बैंक कहीं भी ट्रांसफर कर सकती हैं लेकिन इस बार यह भ्रम टूट गया। "उन्होंने बताया कि सपा का वोट भी हर जगह बसपा को नहीं गया। जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, वहां यादवों ने बीजेपी को वोट दिया है जाटवों ने भी हर जगह गठबंधन को वोट नहीं दिया क्योंकि यदि दिया होता तो शायद ये परिणाम ना आते क्योंकि मुस्लिमों का एकतरफा वोट गठबंधन को ही गया है।"

पिछले साल उपचुनाव में सफलता पाने के बाद सपा और बसपा एक दूसरे के काफी करीब आए और ये नजदीकी राजनीतिक गठबंधन में बदल गई। संयुक्त रैलियां की गईं और मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि 25 साल की राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी अब खत्म हो गई है। लेकिन शायद मतदाता इस संदेश को नहीं ले सके या फिर उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कहती हैं, "सपा और बसपा ने ऊपरी तौर पर तो गठबंधन कर लिया, नेताओं के दिल मिल गए, आपसी झगड़े भी खत्म हो गए लेकिन जमीनी कार्यकर्ता इस मिलन को पचा नहीं पाया।" वर्मा कहती हैं कि दलित समुदाय के लोगों की जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा अदावत यादव समुदाय के लोगों से ही होती है, बाकी कथित ऊंची जातियां भले ही ज्यादा बदनाम हों। ऐसे में यादवों और जाटवों ने कोशिश भले ही की साथ आने की लेकिन पूरी तरह से साथ आ नहीं पाए।

वहीं दूसरी ओर, बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों को लामबंद करने की पूरी कोशिश की तो दूसरी ओर दलितों को भी अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उसने पहले तो इनके जातीय क्षत्रपों की एक फौज तैयार की, उनके महापुरुषों का महिमामंडन किया और फिर जातीय आधार पर बनीं कुछ पार्टियों के साथ तालमेल किया। इन सबके अलावा उज्ज्वला योजना, दो हजार रुपये, आवास और शौचालय जैसी योजनाओं के जरिए लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया और सफल रहे।

यही नहीं, प्रचार–प्रसार के लिए भी बीजेपी ने जिस आक्रामक रणनीति को अपनाया, गठबंधन में वो कहीं नहीं दिख रही थी। पहले चरण के मतदान से कुछ समय पहले दोनों दलों की पहली संयुक्त रैली हुई जबकि उस वक्त तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूपी में दर्जनों बैठकें कर चुके थे। बसपा नेता मायावती तो यूपी की बजाय अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त थीं और कमोवेश यही हाल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का था।

इन सबके अलावा, समाजवादी पार्टी में विभाजन का खामियाजा भी न सिर्फ समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा बल्कि बसपा भी उसकी भुक्तभोगी बनी। यादव लैंड के रूप में समझे जाने वाले इटावा और उसके आस–पास की तमाम सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और इन सभी जगहों पर शिवपाल यादव की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जाहिर है, इन उम्मीदवारों के सारे वोट केवल और केवल गठबंधन के थे। खुद यादव परिवार के तीन अहम सदस्य– डिंपल यादव कन्नौज से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजबाद से चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम के बाद वोटों के जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे साफ है कि बीजेपी को न सिर्फ उसके परंपरागत वोटरों ने वोट दिया बल्कि पिछड़ी जातियों और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा उसके साथ खड़ा हुआ। सुभाष मिश्र यह भी कहते हैं कि कुछ लोग तो गठबंधन की प्रतिक्रिया में बीजेपी की ओर चले गए।

यहां तक कि कांग्रेस को इतने वोट भी नहीं पड़े कि वो किसी तरह मुकाबले में आती या फिर गठबंधन की राह रोक देती। लेकिन कई सीटें ऐसी जरूर हैं जहां सपा और बसपा के वोट ही ट्रांसफर हुए नहीं लगते। सुभाष मिश्र इस संदर्भ में संतकबीर नगर और भदोही सीट का उदाहरण देते हैं जहां दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट मिलने के बावजूद गठबंधन उम्मीदवार की हार हो गई। मिश्र के मुताबिक, "कांग्रेस ने यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया और यादवों का वोट गठबंधन की बजाय कांग्रेस और बीजेपी को चला गया। यादवों ने यदि वोट दिया होता तो गठबंधन उम्मीदवार के हारने की कोई वजह ही नहीं थी। "बहरहाल, इन परिणामों से ये तो तय हो गया है कि सामाजिक समीकरणों को चाहे जितना बिठाने की कोशिश की जाए, राजनीति में ये गणित के जोड़ की तरह परिणाम नहीं दे सकते।

रोहित रावत

परेशानियों में भी जारी रहेगी शिक्षा, एचडीएफसी दे रहा है स्कालरशिप

एचडीएफसी बैंक द्वारा आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे भारतीय मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। "एचडीएफसी बैंक एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट 2019" के तहत ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी पारिवारिक संकट के चलते अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ने को मजबूर हैं वे इस स्कॉलरशिप की सहाय से अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल, कॉलेजों से स्टूडेंट्स का ड्रापआउट रेशियो कम करना है। अनाथ, दिव्यांग, एकल अभिभावक या परिवार में कमाने वाले व्यक्ति जो किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो, उनकी नौकरी चली गई हो, बिजनेस ठप्प हो चुका हो, पिछले तीन वर्ष या इससे कम समय में कमाने वाले परिजन की मृत्यु हो गई हो, ऐसे सभी विद्यार्थी छात्रवृति हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ एक परिवार से केवल एक ही विद्यार्थी को मिलेगा।

मानदंड इस प्रकार हैं:– आवेदक सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त या प्राइवेट स्कूल के छठी से 12वीं कक्षा तक का विद्यार्थी हो या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आईटीआई, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा हो। पिछले तीन वर्षों में स्वयं के या पारिवारिक संकट के चलते शिक्षा जारी रख पाने में असमर्थ हो।

महत्वपूर्ण बिंदु:– इस स्कॉलरशिप के लिए बताए जा रहे निम्नलिखित दस्तावेजो का होना अनिवार्य है।

– पिछली कक्षा की अंकसूची

– एड्रेस प्रूफ, वर्तमान वर्ष का शैक्षिक दाखिला प्रमाण,शिक्षण संस्थान की बैंक डिटेल ,आय प्रमाण–पत्र, जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उसका प्रमाण।

लाभ–ईनाम

10,000 रुपये वार्षिक तक की स्कूल की फीस और 25,000 रुपये वार्षिक तक की फीस ग्रेजुएशन, पीजी, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के संस्थानों को सीधे अदा की जाएगी।

अंतिम तिथि इच्छुक सभी उम्मीदवार 15 जून, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे क इस स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं।

Https://www-buddy4study-com/scholarship/hdfc&educational&crisis&scholarship&2019

श्रेयांश

Vol. 14 **No.** 5
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Rahul Mittal,Bal Krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act. All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

- Clarence Darrow

*****

"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal."

- Henry Ford

*****

"I'll sleep when I'm dead."

- Warren Zevon

*****

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

- Mahatma Gandhi

*****

Compilation:
Priya Kumari

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winners choose what they say;

Losers say what they choose.

*****

Winners truly believe;

Losers only hope.

*****

Winners are always part of the solution;

Losers are always part of the problem.

*****

Winners have a mission;

Losers have excuses.

*****

Winners maximize their strengths;

Losers dwell on their weaknesses.

*****

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**